(3) जब भी खामियां ध्यान में आती हैं खान-पान प्रबन्धकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय पोत परिवहन निगम को हुआ घाटा

*147. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पोत परिवहन निगम में सरकार का कुल पूंजी निवेश कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पोत परिवहन निगम पिछले अनेक वर्षों से लगातार घाटा उठा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो निगम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है, और क्या सरकार ने घाटे को नियंत्रित करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में अब तक 261.23 करोड़ रु. की कुल शेयर पूंजी विनियोजित की है।

(ख) जी, नहीं । भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड 1984-85 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

*148. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक ऐसी परियोजना की बढ़ी हुई लागत कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि संबद्ध विभागों/मंत्रालयों ने लागत में हुई वृद्धि के कारण इन कोयला परियोजनाओं का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान में प्रत्येक 20 करोड़ तथा इससे ऊपर की लागत की क्रियान्वयन अधीन 54 कोयला खनन परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और 17 परियोजनाएं पूरा होने के मामले में कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ग) कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(घ) और (ङ) संशोधित लागत अनुमानों पर अन्तर-मंत्रालयीय समूह में विचार-विमर्श किया जाता है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड में प्रयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है सरकार को संशोधित लागत अनुमानों की स्वीकृति संबंधी सिफारिश प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वृद्धि के कारणों की समीक्षा तथा उन पर विचार-विमर्श किया जाता है ।

विवरण

20·0 करोड़ रु० और इससे ऊपर की लागत की परियोजनाएं

कोयला कंपनी	परियोजना	मूल लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित बढ़ी लागत (करोड़ रु. में)
ई. को. लि.	1. सोनपुर बाजारीडोपनकास्ट	192.96	453.91
	2. झांझरा-भूमिगत	184.55	573.89
	3. धोमो मेन-भूमिगत	73.76	112.00
धा.को.को.लि.	4. ब्लाक–II ओपनकास्ट	112.05	173.84
	5. पुटकी बलिहारी–भूमिगत	199.87	257.64
	6. भालागोरा–भूमिगत	46.22	139.66
से. को. लि.	7. धोरी वेस्ट-गोपनकास्ट	33.30	66.82
ना. को. लि.	8. काकरी–ओपनकास्ट	50.54	137.80
वे. को. लि.	9. सिवेवारा फेस–II भूमिगत	38.00	52.00
सा.ई.को.लि.	10. बेलपहार–ओपनकास्ट	37.88	124.26
	11. दीपका–ओपनकास्ट	56.05	85.92
	12. चूरचा वेस्ट–भूमिगत	32.64	40.18
	13. बालगी–भूमिगत	28.00	30.70
	14. बुंगवार–भूमिगत	25.14	38.23
सी.को.कं.लि.	15. रामागुन्डम–ओ.का.–II	147.16	552.25
	16. जी. डी. के.–10ए–भूमिगत	27.31	122.00
	17. आर. के. –1ए–भूमिगत	29.78	29.78

GOVERNMENT'S REACTION ON PAK SUCCESS IN THE NUCLEAR FREE ZONE RESOLUTION

*149. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the reaction of Government of India on Pakistan's initiative in getting a resolution passed in UN Committee on a Nuclear Free Zone for South Asia; and

(b) what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Pakistan has been sponsoring in the First Committee of the U.N. General Assembly a resolution proposing the establishment of a Nuclear Weapon Free Zone in South Asia every year for the last 17 years. India has been opposing the resolution because nuclear disarmament has to be pursued globally rather than partially and because agreement of all the countries in the region is a prerequisite for such intiatives. India will continue to oppose the proposal.